

SSC GD 2025

अवसर बैच

POLITY

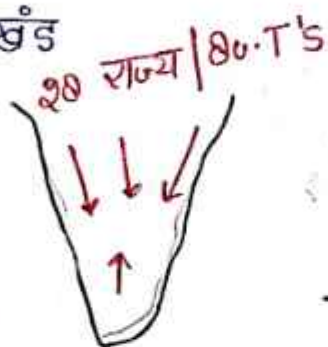
Class - 1

अनुच्छेद - 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नये राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है।

According to article - 3, parliament can form a new state and change the area, boundary or name of an existing state by a simple majority.

ex- बिहार - झारखंड

Art. - 3



Art. - 3 → संसद साधारण बहुमत से Simple majority

U.P. → उत्तराखंड

M.P. → छत्तीसगढ़

→ नये राज्यों का निर्माण

→ राज्यों की सीमा | क्षेत्र | नाम में परिवर्तन कर सकती है।

Simple Majority :-

भाधारण बहुमत \Rightarrow उपस्थित और मतदान
 present and voting $\Rightarrow 50\% + 1$

ex - U.P. \Rightarrow उत्तराखण्ड
 ↓
 Bill (विधेयक) \rightarrow (ex) LS \rightarrow कुल सदस्य $\Rightarrow 543$
 \rightarrow पेश (introduced)

\rightarrow चर्चा (Discussion)

\rightarrow पारित (Pass)

(RS) \rightarrow पेश
 \rightarrow चर्चा
 245 \rightarrow पारित \rightarrow उपस्थित और मतदान

\rightarrow Voting मतदान (M.P.)
 \rightarrow $400 \times 50\% + 1$
 (201)

ex - 200 $\Rightarrow 200 \times 50\% + 1$
 (101)

LS - RS - President राष्ट्रपति \rightarrow signature (हस्ताक्षर)

\rightarrow Uttarakhand राज्य की स्थापना

संसद द्वारा अनुच्छेद - 2 अथवा अनुच्छेद - 3 के अन्तर्गत बनायी गयी विधि अनु. 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन कसे वाली विधि नहीं समझी जायेगी (अनुच्छेद - 4)

ROJGAR WITH ANKIT

A law made by parliament under article 2 or Article 3 shall not be deemed to be a law amending the constitution for the purposes of Article 368 (Article 4)

Art. 4 \Rightarrow Art. 2 & Art. 3 के तहत संसद जी भी कार्य करती है वह Art. 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं है।

Art. 368 \rightarrow संविधान संशोधन की प्रक्रिया

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात

After independence of India \Rightarrow 15 Aug. 1947 \downarrow

भारत के लोगों की मांग \Rightarrow भाषायी आधार पर राज्यों का गठन

Demand of the Indian people \Rightarrow formed of linguistic base States.

\rightarrow डा. राजेंद्र प्रसाद (संविधान सभा के अध्यक्ष)
Chairman of constituent assembly

\Rightarrow धर आयोग का गठन \rightarrow डा. राजेंद्र प्रसाद द्वारा

formed of Dhar commission \rightarrow By Dr. Rajendra Prasad

\rightarrow गठन (formed) \rightarrow जून 1948, अध्यक्ष (Chairman) \rightarrow न्यायमूर्ति एम. के. धर

→ 4 सदस्यीय आयोग
4 members commission

→ कार्य = भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए या नहीं इस पर चर्चा करके रिपोर्ट देना।

→ रिपोर्ट = 10 Dec. 1948, रिपोर्ट में कहा कि भाषा आधारित (Linguistic Base) राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए।

धर आयोग की रिपोर्ट के पश्चात् (After the report of dhar commission)

⇒ JVP समिति का गठन (formed of JVP committee = 1948)

⇒ 3 सदस्य J ⇒ जवाहर लाल नेहरू, V ⇒ वल्लभ भाई पटेल, P ⇒ पट्टाभ्नी सीतारमैया

कार्य (function) → भाषा आधारित राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा (Debate / Discussion) करके रिपोर्ट देना।

⇒ रिपोर्ट (Report) = 1 April 1949, रिपोर्ट में कहा नहीं।

⇒ तेलुगु भाषी (Telugu linguistic) लोगों ने आंदोलन (Protest/Movement) शुरू किया

"विशालांध्र आंदोलन" (Vishala Andhra protest.)

↳ leader (नेता) = पीट्टी श्री रामुल्लु
(Petti Sri Ramullu)

⇒ रामुल्लु ने आमरण अनशन (Death strike / fasting)

↳ 56 days / 56 दिनों तक की शुरुआत की।

भूखे रहने के कारण बीमार

2 दिन (Hospital) अस्पताल में कोमा में रहे।

और 58 days → 15 Dec. 1952 इनकी मृत्यु हो गयी।

तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की माँग का

समर्थन करते हुए पीट्टी श्री रामुल्लु ने आमरण अनशन आरम्भ कर दिया, जिनकी 58

दिनों बाद 15 दिसंबर, 1952 को मृत्यु हो गयी।

Supporting the demand for formation of a separate state on the basis of language for Telugu speakers, Petti Sri Ramullu

Started a fast unto death, who died 58 days later on 15 december 1952.

→ परिषदस्वरूप (As a result) = देश के
प्रधानमंत्री (Prime minister of India) ⇒ Pt. Jawahar Lal Nehru
→ प्रथम भाषा आधारित राज्य
first linguistic base state
↓
→ आंध्र प्रदेश का गठन
Oct. 1953
↓
नै भाषा आधारित (linguistic base) प्रथम राज्य (first state)
= आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की

→ फजल अली आयोग | राज्य पुनर्गठन आयोग
Fazal ali commission | state Re-organisation commission
↳ गठन formed → 1953

↳ Chairman (अध्यक्ष) → न्यायमूर्ति फजल अली

↳ अन्य सदस्य (other members) → 2 →

① लक्ष्मण नाथ कुंजरू

② कै० एम० पनिकर

↳ कार्य → भाषा आधारित राज्यों के गठन की माँग पर चर्चा करना और रिपोर्ट देना।

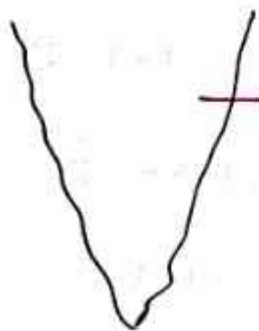
↳ रिपोर्ट (Report) => 30 Dec. 1955

- ① भाषा आधारित राज्यों का गठन नहीं।

↳ Accept (स्वीकार)

② संविधान के भाग - 7 को समाप्त कर दी।

End of the part-7 of constitution



→ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात (After independent of India)

② चार श्रेणियों (4 categories) में विभाजित (Division)

A	क	} End (समाप्त)
B	ख	
C	ग	
D	घ	

Accept स्वीकार => संसद ने 7वाँ

③ 16 राज्यों का संविधान संशोधन (7th constitution Amendment 1956) 1956, के द्वारा शासित प्रदेशों का भाग - 7 (Part-7) को समाप्त कर गठन (formed of दिया।

6 states and 3 U.T's) => Accept (स्वीकार)

=> संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित।

=> State reorganisation Act 1956 passed by Parliament.

↳ 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का

गठन formed of 14 states & 6 U.T's => 1956 (1 Nov. 1956)

नये राज्यों का गठन

राज्य	गठन वर्ष
आंध्र प्रदेश	1 October, 1953 ई.
गुजरात → 15वाँ	1 मई, 1960 ई.
भारत → 16	1 दिसंबर, 1963 ई.
हरियाणा → 17	1 नवंबर, 1966 ई.
हिमाचल प्रदेश → 18	25 जनवरी, 1971 ई.
मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा (1972) ↓ 19 20 21	21 जनवरी 1972 ई.
सिक्किम → 16 मई, 1975 ई. (22वाँ राज्य)	
मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 24 → 20 फरवरी, 1987 ई.	
गोवा → 25वाँ राज्य (56वाँ 1987)	30 मई 1987
छत्तीसगढ़ → 26वाँ	1 नवंबर, 2000
उत्तराखण्ड → 27वाँ	9 नवंबर, 2000
झारखण्ड	15 नवंबर, 2000
तेलंगाना	2 जून, 2014

सिक्किम
 ↳ 36वाँ संविधान
 संशोधन 1975

→ 31 Oct. 2019 → JK
 (लद्दाख) (जम्मू कश्मीर)

→ 2019 से पहले राज्य (State) था।
 ↓
 2019 ↑
 ↓
 राज्य = 29
 - JK ①

 28
 5 राज्य

2 नये केंद्र शासित प्रदेश

1956 → ⑥

26 Jan. 2020

→ 7 वां → पुदुचेरी → 1962

→ JK
 → लद्दाख > 7+2 ⇒ ⑨

- ① दिल्ली
- ② पुदुचेरी
- ③ JK
- ④ लद्दाख

- ⑤ चण्डीगढ़
- ⑥ Andaman & निकोबार
- ⑦ लक्षद्वीप
- ⑧ दादर नागर हवेली
- ⑨ वमन दीव

① 26 Jan. 2020 को
 दोनों का विलय (Merge)

9-1 ⇒ ⑧